NYAY से अभिप्राय

लेखक - जीन द्रेज (प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, रांची विश्वविद्यालय)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (सामाजिक मुद्दे)

इंडियन एक्सप्रेस

5 अप्रैल, 2019

"इसे सामाजिक सुरक्षा के लिए एक राजनीतिक वादे के रूप में समझा जा सकता है। इसे भुनाने के एक से अधिक तरीके हैं।"

न्यूनतम आय की गारंटी एक बेहतर विचार है जो पहले से ही विभिन्न देशों में प्रमुख बन चुका है। उदाहरण के लिए, कुछ यूरोपीय देश अपने नागरिकों को न्यूनतम आय की गारंटी देते हैं। इसके लिए सूचना और डेटा संग्रह सेवाओं के व्यापक संग्रह की आवश्यकता होती है।

यदि भारत में भी ऐसी पहल की शुरुआत की जाती है, तो यह सबके लिए बेहतर साबित होगा,लेकिन इसके समक्ष कई बाधाएं भी मौजूद हैं जिन पर कार्य करने की आवश्यकता है। वित्तीय बोझ के साथ, नितिन भारती और लुकास चैनल द्वारा हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वालिटि लैब का संक्षिप्त विवरण कुछ उपयोगी आंकड़े प्रस्तुत करता है। लेखक न्यूनतम आय का आकलन करते हैं, जो न्यूनतम आय और वर्तमान आय के बीच का अंतर है।

प्रति वर्ष 72,000 रुपये की न्यूनतम आय के साथ, यह अंतर सकल घरेलू उत्पाद का 1.3 प्रतिशत हो जाता है। यह जानकारी सहायक है, लेकिन यह इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं देता है कि सभी को प्रति वर्ष न्यूनतम आय 72,000 रुपये से देने के लिए इसकी लागत क्या होगी। कईयों का मानना है कि अगर यह पूरी तरह से लक्षित और नि:शुल्क टॉप-अप हस्तांतरण के माध्यम से किया जाता है, तो यह सकल घरेलू उत्पाद का 1.3 प्रतिशत होगा।

शुरुआत में, कांग्रेस पार्टी की न्यूनतम आय गारंटी (MIG) इसी मॉडल पर आधारित थी। इनका विचार था कि यदि न्यूनतम आय और वास्तविक आय के बीच किसी प्रकार का अंतर होता है, तो सरकार इस अंतर को खत्म करे। यह अव्यावहारिक है, केवल इसलिए क्योंकि इसके लिए परिवार-विशिष्ट आय डेटा की आवश्यकता होती है जो कि कम से कम वर्तमान में एकत्र करना असंभव है।
यह स्पष्ट प्रोत्साहन समस्याएं भी पैदा करता है। एक संभावित प्रतिक्रिया यह है कि अंतर की गणना करने का आधार वास्तविक आय नहीं, बल्कि अध्यारोपित आय (एक परिवार में अवलोकन योग्य विशेषताओं के आधार पर अपेक्षित आय, जैसे - शिक्षा और भूमि का स्वामित्व) होनी चाहिए। हालांकि, अध्यारोपित आय का अनुमान स्पष्टता की कमी से ग्रसित है, जो बड़े समावेश और अपवर्जन त्रुटियों का कारण बनता है।

इन सब कारणों से, टॉप-अप फॉर्मूला को त्याग दिया गया था और एनवाईएवाई की घोषणा की गई थी: प्रति वर्ष 72,000 रुपये की समान नकद हस्तांतरण अर्थात् प्रति माह 6,000 रुपये, 20 प्रतिशत गरीब परिवारों को (2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लगभग 50 करोड़ परिवार) दिया जायेगा। प्रारंभ में, एक धारणा बनाई गई थी कि NYAY (न्यूनतम आय योजना)प्रति माह 12,000 रुपये की 'गारंटी' प्रदान करेगी, क्योंकि अधिकांश परिवार अपने दम पर कम से कम 6,000 रुपये कमा ही लेते हैं, लेकिन यह गलत है।

वास्तव में, भारती और चांसेल ने अनुमान लगाया है कि 2011-12 में 33 प्रतिशत परिवारों ने 6,000 रुपये प्रति माह से कम की कमाई की है और अगर वर्तमान की बात करें तो अभी के समय में अनुपात और अधिक होगा। संक्षेप में, NYAY एक लक्षित नकदी-हस्तांतरण योजना है, जो प्राप्तकर्त्ताओं को प्रति माह 6,000 रुपये की गारंटी देती है, जो न ही कम है और न ही अधिक है। इसे बड़े पैमाने पर गैर-अंशदायी पेंशन योजना के रूप में भी विचार किया जा सकता है।

स्वाभाविक रूप से, NYAY टॉप-अप फॉर्मूला से अधिक महंगा है। इसके लिए प्रति वर्ष 360,000 करोड़ रुपये या आज की जीडीपी के 2 प्रतिशत के करीब की आवश्यकता है। यदि NYAY को पाँच साल तक कायम रखा जाता है और भारत की वास्तविक

जीडीपी प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की दर से बढ़ती रहती है, तो लागत सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 1.4 प्रतिशत होगी। अगर यह वास्तव में सबसे गरीब परिवारों को जाती है, तो NYAY एक अच्छी पहल साबित होगी। हालांकि, NYAY के प्राप्तकर्त्ताओं की पहचान कैसे की जाती है, यह एक अनसुलझी पहेली है।

देखा जाये, तो बीपीएल सर्वेक्षणों का रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि तीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण बताते हैं कि 2004-05 में उनके पास बीपीएल कार्ड नहीं थे। हाल के वर्षों में, कुछ राज्यों ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है, जिसे 'अपवर्जन दृष्टिकोण' के रूप में जाना जाता है। इस दृष्टिकोण में, अच्छी तरह से समृद्ध परिवारों को सरल और पारदर्शी मानदंडों का उपयोग करके बाहर रखा गया, जिससे बाकी सभी डिफॉल्ट रूप से पात्र हो गये। यह दृष्टिकोण बीपीएल सर्वेक्षणों की तुलना में बहुत बेहतर काम करता है, लेकिन तब जब विशेष रूप से परिवारों का अनुपात अपेक्षाकृत कम हो अर्थात् 20 या 25 फीसदी तक। लेकिन 80 प्रतिशत को छोड़ना, जैसा कि NYAY को आवश्यकता है, एक और मामला बनता है।

लक्ष्यीकरण समस्या अभी अधिक गंभीर है क्योंकि NYAY के तहत प्रस्तावित किए जा रहे आय हस्तांतरण बीपीएल परिवारों को दी गई किसी भी चीज से बहुत बड़ा है। यह चौंका देने वाला है कि प्रति माह 6,000 रुपये का वेतन गरीब राज्यों के कई अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों (जैसे-चौकीदारों या घरेलू श्रमि) के लिए बहुत है। लोग इसी तरह की नौकरी या इतना ही कमाने के लिए काफी संघर्ष करते हैं, घूस देते हैं, धोखा देते हैं और लड़ते भी हैं। 6,000 रुपये जैसी बिना शर्त वाली मासिक पेंशन के लिए केवल 20 प्रतिशत परिवारों का चयन करना अराजकता का आभास कराता है।

शायद आगे की राह एक बड़ी पेंशन योजना के लिए एक राजनीतिक प्रतिबद्धता के रूप में है, जो 20 प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों को प्रति माह 6,000 रुपये नकद हस्तांतरण के बराबर है और इस सूत्र के संभावित रूपों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, एक संभावित रूप में 5 करोड़ परिवारों के लिए 6,000 रुपये प्रति माह के बजाय 25 करोड़ व्यक्तियों के लिए प्रति माह 1,200 रुपये की व्यक्तिगत पेंशन शामिल होगी। NYAY पेंशनभोगी सभी बुजुर्ग व्यक्तियों, एकल महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को शामिल कर सकते हैं, जो अच्छी तरह से निर्दिष्ट अपवर्जन मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। इससे कम से कम 12 करोड़ लोग और जुड़ जायेंगे, जिससे अन्य कमजोर श्रेणियों को पर्याप्त जगह मिल जाएगी। हालांकि, यह सही नहीं है, लेकिन कम से कम यह काम तो करेगा।

अन्य प्रकार भी संभव हैं। उदाहरण के लिए, घरेलू और व्यक्तिगत पेंशन का मिश्रण। राजनेताओं को सरल नारों की आवश्यकता होती है और 'प्रति वर्ष 20 प्रतिशत गरीब परिवारों के लिए 72,000 रुपये की धनराशि' इस उद्देश्य को पूरा भी करती है, लेकिन NYAY (एनवाईएवाई) प्रस्ताव की राजनीतिक प्रतिबद्धता को बहाल करना महत्वपूर्ण है।

GS World Committed To Excellence

GS World टीम...

न्यूनतम आय योजना (न्याय, NYAY)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में कांग्रेस ने देश की 20 फीसदी सबसे गरीब आबादी को सालाना 72,000 रुपये की मदद देने का वादा किया है और इसे श्न्यूनतम आय योजनाश का नाम दिया गया है।
- कांग्रेस की गणना के मुताबिक, देश में 12000 से कम कमाने वाले करीब पांच करोड परिवार हैं।
- प्रति परिवार पांच आदमियों के औसत से इसके लाभार्थियों की संख्या 25 करोड़ बताई गई है जो देश की जनसंख्या का करीब 20 फीसदी होती है।

मुख्य बिंदु

- कांग्रेस के आंकड़ों को ही आधार मान लें तो साल में 72000 रुपये पांच करोड़ परिवारों को देने में 3.6 लाख करोड़ रुपये का सालाना खर्च आएगा।
- मोटे अनुमान के मुताबिक, यह देश की कुल जीडीपी का 1.3 प्रतिशत और मौजूदा वार्षिक बजट का 13 फीसद है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी, 2019 को गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का शुभारंभ किया गया।
- लघु एवं सीमांत कृषकों की आय बढ़ाए जाने एवं उनके सुनहरे भविष्य के लिए इस योजना को भारत सरकार ने पूरे देश में लागू किया है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का शुभारंभ किया है।

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) की घोषणा 1 फरवरी, 2019 को अंतरिम बजट 2019-20 को की गई थी।
- इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त जोत/ स्वामित्व वाले छोटे एवं सीमान्त कृषक परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए दिए जाएंगे।

मुख्य बिंदु

- यह राशि 2000 रुपए प्रत्येक की तीन किस्तों में दी जाएगी।
- यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। डीबीटी पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और किसानों का समय बचाएगा।
- प्रधानमंत्री-किसान योजना भारत सरकार से 100 प्रतिशत वित्त पोषण प्राप्त एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। योग्य लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए अंतरण हेतु यह योजना 01.12.2018 से प्रभावी हो गई है।
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेशों) में मौजूदा भूमि-स्वामित्व प्रणाली का उपयोग लाभार्थियों की पहचान के लिए किया जाएगा। 01 फरवरी, 2019 तक जिनके भी नाम भूमि रिकॉर्ड में होंगे, उन्हें इस योजना का लाभ लेने का पात्र माना जाएगा।

उद्देश्य

- प्रधानमंत्री-किसान योजना का उद्देश्य प्रत्येक फसल चक्र की समाप्ति पर अनुमानित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य एवं उपयुक्त उपज सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न निविष्टियों को प्राप्त करने में एसएमएफ की वित्तीय आवश्यकताओं में सहायता प्रदान करना है।
- यह उन्हें ऐसे व्ययों की पूर्ति के लिए सूदखोरों के चंगुल में फंसने से बचाएगी तथा कृषि कार्यकलापों में उनकी नियमितता भी सुनिश्चित करेगी।

किसे नहीं मिलेगा लाभ?

- यदि किसी किसान परिवार के एक या अधिक सदस्य निम्न श्रेणियों, किसी संस्थागत पद पर पूर्व में या वर्तमान में कार्यरत, मौजूदा या पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा-राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद् के पूर्व या मौजूदा सदस्य, नगर निगमों के पूर्व या मौजूदा मेयर और जिला पंचायतों के मौजूदा या पूर्व चेयरपर्सन में आते हैं, तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- केंद्र और राज्य सरकारों के मौजूदा या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अलावा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (इसमें मल्टी टास्किंग कर्मचारी-श्रेणी चार-समूह डी के कर्मचारी शामिल नहीं हैं) को भी इस योजना का फायदा नहीं मिल सकेगा।
- ऐसे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी या पेंशनभोगी, जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए या उससे अधिक है, को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'न्यूनतम आय योजना' (एनवाईएवाई) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. यह लक्षित नकदी-हस्तांतरण योजना हैं, जो प्राप्तकर्ताओं को प्रति माह 6000 रूपये की गारंटी देता है।
2. इससे प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

1. Consider the following statements in the context of Nyuntam Aay Yojana (NYAY):-

1. It is a targeted cash transfer scheme which gives the guarantee of Rs. 6000 per month to beneficiaries
2. Every year 20% poor family will get its benefit.

Which of the above statement is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) 1 and 2 Both (d) Neither 1, Nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: न्यूनतम आय योजना (एनवाईएवाई) अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों को आर्थिक रूप से सशक्त करने में किस प्रकार बेहतर साबित होगा? चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

Q. How the Nyuntam Aay Yojana (NYAY) will prove better in economically empowering the workers work in unorganised sector? Discuss.

(250 Words)

नोट : 4 अप्रैल को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b), 2 (a) होगा।